IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

''भारत सरकार के बजट घाटे की प्रवृत्तियाँ एवं घाटे के वित्तपोशण के स्रोत्र का समालोचनात्मक अध्ययन''(भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत पिछले बजटो के वि"ोश संदर्भ में)

डॉ0 आलोक सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर
वाणिज्य संकाय,
श्री गणे"ा राय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
डोभी, जौनपुर(यू0पी0)

सारः—
घाटे का वित्त प्रबन्ध अर्थव्यवस्था में कई प्रकार के प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। घाटे के वित्त प्रबन्ध से सामान्यतः कीमत स्तर में वृद्धि होती है वही आय एवं धन के वितरण पर भी महत्वपूर्ण पभाव पडता है।.'भारत एक विकास"ील दे"ा है जो विकास के पथ पर अग्रसारित है। अब प्र"न यह उठता है कि घाटे के वित्त प्रबन्ध से हमारे दे"ा के विकास पर क्या प्रभाव पडता है। इस प्रभाव में सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनो रूपों में देखा जा सकता है। घाटे के सही वित्त प्रबन्ध द्वरा जहाँ रोजगार, निवे"ा, उत्पादन, अर्थव्यवस्था आदि पर स्वाथ्य वर्धक प्रभाव पडता है वही इसका प्रबन्धन ठीक प्रकार से नही होने पर स्फीतिक, वेरोजगारी निवे"ा आदि पर हानि कारक प्रभाव पडता हैं। भारत में जहाँ कुछ क्षेत्रों में मंदी की स्थिति है तो कुछ क्षेत्रो में उछाल की स्थिति है ऐसे में भारत सरकार द्वारा घाटे के वित्त प्रबन्ध का सही से प्रयोग नही किया गया तो, इसका लाभ के बदले हानि हो सकाता है। घाटे के वित्त प्रबन्ध की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि निव"ोां तथा उत्पाद के बीच के समय में स्फीति को किस प्रकार तथा किस सीमा तक दूर रखा जा सकता है। निवे"ा तथा उत्पाद में वृद्धि के बीच समय अन्तराल जितना कम होगा और उत्पादन के लिए पूंजी की आव"यकता जितनी कम होगी उतनी ही घाटे के वित्त प्रबन्ध के कारण उत्पन्न होने वाली स्फीति प्रभाव कम होगी। आर्थिक विकास में घाटे क वित्त प्रबन्ध के उचित योगदान देने की सामर्थ्य उस स्थिति में समाप्त हो जाती है जबकि घाटे के वित्त स्फीति के कारण, स्फीतिकारी वित्त मे बदल जाता है। बढती हुई किमतों की स्थिति में लग—भग सभी क्षेत्रों में अधिकाधिक निवे"ा करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, परिणाम यह होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में साधनो का स्थानान्तरण कठीन हो जाता है।

भूमिकाः—

वर्तमार समय में घाटे का वित्त प्रबन्ध, सार्वजनिक वित्त प्रबन्ध का वि"ोशकर अर्द्ध—विकसित राश्ट्रो के लिए जो विकास के पथ पर आगे बढ़ने की ओर अग्रसर है, एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। वास्तव में घटे के वित्त प्रबन्ध का आ"ाय विभिन्न दे"ाों में संकटकालीन परिस्थितियों, जैसे मंदी, युद्ध आदि के दौरान वित्त के अतिरिक्त साधनों के जुटाव के लिए किया जाता है। 19वी भाताब्दी तक घाटे के वित्त का भारतीय बजटीय व्यवस्था में कोई वि"ोश स्थान नही था लेकिन 20वी भाताब्दी में इसका महत्व बढने लगा और वर्तमान समय में भारतीय बजटीय व्यवस्था का एक अभिन्न अंग बनचुका है।

घाटे की वित्त प्रबन्ध की संकल्पना :—

घाटे का वित्त प्रबन्ध एक ऐसी प्रकिया है, जिसके द्वारा सरकार बजट के घाटे को ऋण लेकर अथावा अधिक नोट प्रकाि"ात करके पूरा करती है। साधारणतय बजट घाटे उस स्थिति के सूचित करते है जबकि सरकार का कुल व्यय कुल आय की अपेक्षा अधिक हो।

भारत में घाटे की वित्त–व्यवस्था से आ"ाय सरकार द्वारा अपने व्यय को अधिक नोट छापकर या ऋण लेकर पूरा करने स है। पि"चमी दे"ाों में बजट के घाटे की पूर्ति ऋणों द्वारा करने पर उसे घटे की वित्त–व्यवस्था कहते है।[1] इस घाटे को अनेक ढग से पूर्ण किया जजा सकता है। जैसे– विदे"ाों से ऋण लेकार, अतिरिक्त मुद्रा प्रसार करके एवं आन्तरिक ऋण लेकर आदि। भारत में घाटे के प्रबन्ध भाब्द का उपयोग बजट के घाटे द्वारा सकल राश्ट्रीय व्यय में प्रत्यक्ष वृद्धि से किया जाता है, चाहे यह कमी आयगत हो या पूंजीगत खाते से हो।

बजट के घाटों के सम्बन्ध में कई विचार देखने को मिलते है– प्रथम संकल्पना घाटे की सार्वजनिक ऋण संकल्पना ह इस विचारधारा के अनुसार जब सरकार का व्यय, पूंजी व्यय को सम्मिलित करते हुए कुल आय से अधिक हो और घाटे की पूर्ति ऋणों के द्वारा की जाय तथा प्रत्येक बर्श नये ऋणों की रा"ि घाटे की रा"ि के बराबर हो तो इस विधि को घाटे की वित्त प्रबन्ध कहते है। जबकि दूसरी विचार धारा के अनुसार जब सरकार सम्पत्ति में होने वाले निवल ह्रास को पूरा करने तथा सम्पत्ति में निवल वृद्धि करने हेतु बजट के घाटे को ऋण द्वारा पूरा करती है तो उसे घाटे का वित्त प्रबन्ध कहते है। दूसरे भाब्दों में, चालू आय तथा व्यय का अन्तर ऋणों की मात्रा की निवल वृद्धि के बराबर होगा। इसे घाटां की निवल मूल्य संकल्पना कहते है।

भारत में घाटे का वित्त प्रबन्ध बजट के घाटे को सूचित नही करता है। यह उस स्थिति का बोध करता है जबकि सरकार का व्यय उसकी समस्त आय, अर्थात करो, सार्वजनिक उद्योगों से प्राप्त लाभों, जनता द्वारा प्राप्त ऋणों, जमाओं तथा कोशों एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त आय से भी आधिक हों जाय।[2]

भारत सरकार के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था का उद्दे"यः–

भारत सरकार द्वारा घाटे की वित्त व्यवस्था का उपयोग बजट घाटे के द्वारा सकल राश्ट्रीय आय में प्रत्यक्ष वृद्धि करना ह। इसके अलावा प्रमुख उद्दे"य निम्न है–

1–मूल्य स्तर को बनाये रखने के लिएः– जब सरकार बजट घाटे को पूरा करने के लिए केन्द्रीय बैक से ऋण लेती है ता बैकों में पडी पूंजी सकिय हो जाती है औ इससे मूल्य स्तर उपर उठने लगता है। मंदी काल में हिनार्थ प्रबन्ध द्वारा ही मूल्य स्तर उपर उठाने मे सहायता मिलती है।

2–प्रकृतिक संसाधनो को विकसित करने मेंः– भारत सरकार हिनार्थ प्रबन्ध का उपयोग अपने प्राकृतिक संसाधनो का विकसित करने में करती है

3–आर्थिक विकास करने के लिएः– वि"व के समस्त अर्द्ध–विकसित दे"ाों में आर्थिक विकास के कार्यक्रम बनाये जाते है, जिसे पूर्ण करने के लिए दे"ा के पास प्रर्याप्त मात्रा मे आर्थिक साधन उपलब्ध नही होते , ऐसी परिस्थिति में में विकास योजनाओं की वित्तीय व्यवस्था के लिए उस दे"ा की सरकार को घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा लेना पडता है। भारत सरकार भी आपने आर्थिक विकास के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा लेना पडता है।

4–मंदी वा बेकारी को रोकने के लिए

5–युद्ध का संचालन करने के लिए

भरत में घाटे की वित्त व्यवस्था की माँपः–

साधारण बोल चाल की भाशा में 'घाटे की वित्त व्यवस्था' का अर्थ आय की तुलना में व्यय का अधिक होना है। आधुनिक काल में घाटे की वित्त–व्यवस्था, सार्वजनिक वित्त–प्रबन्धन का वि"ोशकर अर्द्ध–विकसित राश्ट्रों के लिए, जो विकास के पथ पर आगे बढ़ने की चेश्टा में लगे हुए है राजस्व का एक महत्त्पूर्ण स्त्रोत बन गया है। घटे का वित्त प्रबन्धन एक ऐसी क्रिया है, जिसके द्वारा सरकार बजट के घाटों को ऋण लेकर अथवा अधिक नोट छाप करके पूरा करती है। साधारणतया बजट के घाटे उस स्थिति को सूचित करता है जबकि सरकार का कुल व्यय आय से अधिक होता है। भारत सरकार के बजट में विभिन्न प्रकार के घाटे का प्रयोग किया गया है जिसका वर्णन निम्नवत है–

(1) राजस्व घाटाः– राजस्व या आगम घाटा वह होता है जिसमें सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ राजस्व व्यय से कम होता है, तो उसे राजस्व घाटा कहा जाता है। राजस्व व्यय में वह खर्च सम्मिलित होता हे जो किसी प्रकार की परिसम्पत्ति सृजित नहीं करता है।

राजस्व घाटा = राजस्व व्यय – राजस्व प्राप्तियाँ

(2) प्रभावी राजस्व घाटा :– यह राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियो के सृजन हेतु अनुदान को घटाने के बाद प्राप्त होता है।

प्रभावी राजस्व घटा = राजस्व घटा – पूंजी परिसंपत्तियो के सृजन हेतु अनुदान

(3) राजकोशीय घटा :–मौद्रिक प्रणाली पर गठित सुख्मय चक्रवर्ती समिति की रिपोर्ट के प"चात् सन् 1986 मे राकोशीय घाटे की यह अवधारणा सामने आई जिसमें सरकार की आन्तरिक एवं बाहरी ऋण भार जैसे–बाजार ऋण, लधु बचत, भविश्य निधि बजटीय घाटे में सम्मिलित किया जाता है। यह कुल व्यय में से राजस्व प्राप्तियाँ, ऋणो की वसूली एवं अन्य प्राप्तियाँ घटाने के बाद प्राप्त होता है।

राजकोशीय घाटा = कुल व्यय – (राजस्व प्राप्तियाँ + ऋणो की वसूल + अन्य प्राप्तियाँ)

= बजेटरी घाटा + सार्वजनिक ऋण एवं अन्य देयतायें

(4) प्राथमिक घाटा :– भारत के बजट में प्राथामिक घाटा की गणना, राजकोशीय घाटे में से ब्याज के भूगतान को घटा कर किया जाता है। प्राथमिक घाटा दो प्रकार का होता है। जिसका वर्णन निम्न है

प्राथमिक घाटा = राजकोशीय घाटा – ब्याज भूगतान

(I) प्राथमिक घाटा(उपभोग) :– प्राथमिक घाटा (उपभोग) की गणना राजस्व घाटे मे से ब्याज भुगतान, प्राप्तियाँ, लाभां"ा एवं लाभ घटाने पर प्राप्त होता है।

प्राथमिक घाटा(उपभोग) = राजस्व घाटा – (ब्याज भुगतान + प्राप्तियाँ + लाभां"ा + लाभ)

(II) प्राथमिक घाटा(निवे"ा) :– प्राथमिक घाटा निवे"ा की गणना पूंजीगत व्यय में से ब्याज प्राप्तियाँ, लाभ, लाभां"ा, ऋण वसूली तथा अन्य प्राप्तियाँ घटाने पर प्राप्त होता है।

प्राथमिक घाटा(निवे"ा) = कुल पूंजीगत व्यय – (ब्याज प्राप्तियाँ + लाभ/लाभां"ा + ऋण वसूली + अन्य प्राप्तियाँ)

(5) बजटीय घाटा :–जब सरकार का कुल व्यय, उसकी कुल प्राप्तिया से अधिक हो जाता है तों उसे बजट घाटा कहा जाता है। भारत सरकार के बजट से सन् 1997–98 से इस अवधारणा का परित्याग कर दिया गया है। बजटीय घाटा की गणना कुल प्राप्तियों में से कुल व्यय घटाने के बाद प्राप्त होता है।

बजटीय घाटा = कुल प्राप्तियाँ – कुल व्यय

भारत सरकार के घाटे के प्रवृत्ति का अध्ययनः–

भारत सरकार के 2012–13 से 2021–22 तक के प्रमुख घाट

(भारत सरकार के 2012–13 से 2021–22 तक के कुल व्यय, राजस्त घाटा, प्रभावी राजस्त घाटा,राकोशीय घाटा एवं प्रथमिक घाट) (₹करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	कुल–व्यय	राजस्व घाटा	प्रभावी राजस्व घाटा	राजकोषीय घाटा	प्राथमिक घटा
2012–13 वास्त.	1410372	364282	248572	490190	177020
2013–14 वास्त.	1559447	357045	227630	502858	128604
2014–15 वास्त.	1663673	365519	234759	510725	108218
2015–16 वास्त.	1790783	342736	210982	532791	91132
2016–17 वास्त.	1975194	316381	150648	535618	54904
2017–18 वास्त.	2141973	443600	252566	591062	62110
2018–19 वास्त.	2315113	454483	262702	649418	66770
2019–20 वास्त.	2686330	666545	480904	933651	321581
2020–21 संसांधित अनुमान	3450305	1455989	1225613	1848655	1155755
2021–22 बजट अनुमान	3483236	1140576	921446	1506812	697111
औसत.	2247642.6	590715.6	421582.2	810178	286320.5

(स्त्रोत–भारत सरकार के बजट दस्तवेज–बजट सार वित्तीय वर्श 2012–13 से 2021–22 तक)

उपरोक्त तालिका में भारत सरकार के कुल व्यय के सापेक्ष राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, राजकोशीय घाटा एवं प्राथमिक घाटा को ₹करोड़ मे दिखाया गया है। वित्तीय वर्श 2012–013 में राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, राजकोशीय घाटा एवं प्राथमिक घाटा क्रम"ाः ₹364282, ₹248572, ₹490190 एवं ₹177020 करोड़ है जिसमे वार्शिक वृद्धि में उतार–चढ़ाव के साथ वित्तीय वर्श 2021–22 के बजट अनुमान में राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, राजकोशीय घाटा एवं प्राथमिक घाटा बढ़ कर क्रम"ाः ₹1140576, ₹921446, ₹1506812 एवं ₹697111 करोड़ हो गया है। अगर इसका औसत निकाला जाय तो राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, राजकोशीय घाटा एवं प्राथमिक घाटा क्रम"ाः ₹590715.6, ₹421582.2 , ₹810178 एवं ₹286320.5 करोड है। जो यह स्पश्ट करता है कि सरकार सभी प्रकार के घाटे में बढ़ने की प्रवृति रही है।

भारत सरकार के घाटे की प्रवृत्तियाँ सकल घरलू उत्पाद के रूप में:[3]–

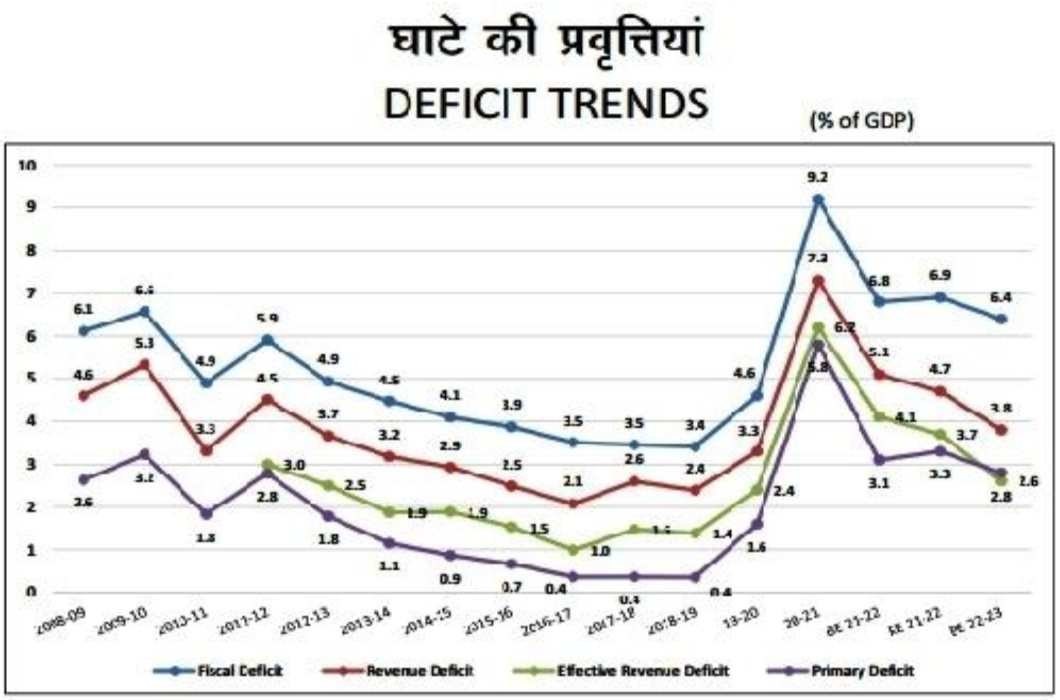

उपरोक्त चार्ट को देखने से स्पश्ट होता है की भारत सरकार का राजकोशीय घाटे में काफी उतार चढॉव हुआ है। वित्तीय वर्श 2008–09 में राजकोशीय घाटा सकल घरलू उत्पाद के 6.1 प्रति"ात था जो घट कर 2019–20 में 3.4 प्रति"ात हो गया तथा पुनः 2021–22 के बजट अनुमानो में आपने उच्चतम स्तर पर बढकर सकल घरेलू उत्पाद के 9.2 प्रति"ात हो गया लेकिन सरकार द्वारा उपचारात्मक उपाय किये जाने के कारण यह

पुन घटकर 2022–23 बजट अनुमानो में 6.4 प्रति"ात हो गया। इस प्रकार हम देखते है कि राजकोशीय घाटे में उतार चढॉव के साथ अन्नतः बढने की प्रवृत्ति ही रही है।

भारत सरकार का राजस्व घाटा वित्तोय वर्श 2008–09 में सकल घरेलू उत्पाद के 4.6 प्रति"ात था जो वित्तीय वर्श 2019–20 में अपने न्यूतम स्तर 2.4 पर आ गया था लेकिन 2020–21 में पुनः बढकर आपने उच्चतम स्तर 7.3 पर पहुच गया। राजकोशीय घाटे मे 2022–23 में सुधार होने का असर राजस्व घाटे पर भी पडा जा घट कर 3.8 प्रति"ात हो गया। भरत सरकार का प्रभावी राजस्व घाटा 2011–12 में सकल घरेलू उत्पाद का 3.0 प्रति"ात था जो वित्तीय वर्श 2018–19 में घटकर अपने न्यूतम स्तर 1.4 पर आ गया था लेकिन अगले ही वर्श यानी वित्तीय वर्श 2019–20 में पुनः अपने उच्चतम स्तर 6.2 पर पहच गया। प्रभावी राजस्व घाटे को 2022–23 के बजट अनुमानों में सकल घरेलू उत्पाद के 2.6 प्रति"ात रहने का अनुमान है।

भारत सरकार का प्राथमिक घाटा वित्तय वर्श 2008–09 में सकल घरेलू उत्पाद का 2.6 प्रति"ात था जो घटते–घटते अपने न्यूतम स्तर 0.4 प्रति"ात, वित्तीय वश 2018–19 में हो गया, लेकिन वित्ती वर्श 2020–21 मे अपने उच्चतम स्तर 5.8 प्रति"ात हो गया तथा 2022–23 के बजट अनुमानो में इसे पुनः बढकर 2.8 प्रति"ात होने का अनुमान है। उपरोक्त चार्ट से स्पश्ट है कि राजकोशीय घाटा, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा एवं प्रथमिक घाटे में उतार चढाव के साथ बढने की ही प्रवृत्ति रही है।

भारत सरकार के घाटे का वित्तपोशण के स्रोतः–

भारत सरकार के घाटे का वित्तपोशण के स्रोत को निम्न चार्ट द्वारा दिखाया गया है–

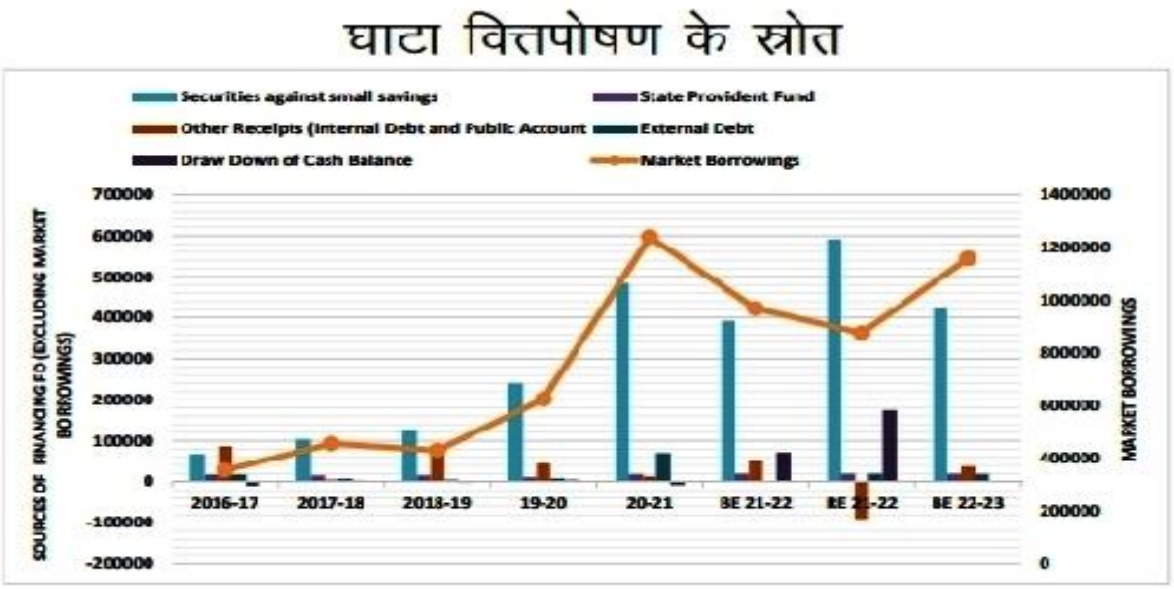

भारत सरकार के घाटे के वित्तपोशण में सिक्योरटी अगेन्सड लघु बचत का महत्वपूर्ण योगदान है वित्तीय वर्श 2016–17 में इसका योगदान लग–भग 7 लाख करोड था जो वित्तीय वर्श 2021–22 के बजट अनुमानों में बढकर 12 लाख करोड़ हो गया तथा पुनः 2022–23 के बजट अनुमानो में घटकर 9 लाख करोड़ हो गया। स्टेट पोविडेन्ट फन्ड द्वारा भारत सरकार के घाटे का वित्तपोशण में औसत रूप से 2 लाख करोण का योगदान घट–बढ के साथ रहा है। घाटे के वित्तपोशण में अन्य प्राप्तियों का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है वित्तीय वर्श 2016–17 में जहाँ इसका योगदान 8 लाख करोड़ से अधिक रहा है वही 2022–23 के बजट अनुमानों में 2 लाख के आस–पास हो गया है। भारत सरकार के घाटे के वित्तपोशण में बाह्य ऋण तथा ड्रॉ डाउन ऑफ कैस वैलेन्स का कुल वित्तपोशण में बहुत ही कम महत्व रहा है वही बाजार उधारी का महत्वपूर्ण स्थान रहा है वित्तीय वर्श 2016–17 मे बाजार उधारी का हिस्सा दो लाख से भी कम था जो 2022–23 के बजट अनुमानो में बढकर 11 लाख के पास पहुच गया है।

उपरोक्त वि"लेशण से स्पश्ट है की भारत सरकार के घाटे के वित्तपोशण मे सिक्योरटी अगेन्स स्मॉल सेविंग एवं बाजार उधारी का महत्वपूर्ण स्थान है वही अन्य प्राप्तियों एवं बाह्य ऋण का नागण्य स्थान है।

निश्कर्शः– उपरोक्त वि"लशण से स्पश्ट हो जाता है की भारत सरकार द्वारा घाटे के वित्त का सहारा अपने बजट में महत्वपूर्ण अस्त्र के रूप में लिया है। चाट को देखने से स्पश्ट है कि इसमें लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति रही है जो इस बात की ओर संकेत करता है कि बजट दर बजट घाटे के वित्त पर सरकार की निर्भरता बढी है। वही घाटे के वित्तपोशण में बाजार उधारी पर भी निर्भरता बढी है। घाटे के वित्त का प्रभाव देखा जाय तो इसका सबसे बडा प्रभाव मुद्र के स्तर पर पड़ा है जिसमें लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति रही है वही व्यक्तियों के आय एवं बचत पर भी नाकारात्मक प्रभाव पिछले दसको में देखने को मिला है। घाटे के वित्त प्रबन्ध से आय एवं धन के वितरण पर भी नाकारात्मक प्रभाव पड़ा है तथा अमीर एवं गरीब के बीच खाई भी बढी है। यह स्पश्ट रूप से कहा जा सकता है कि भारत सरकार द्वारा घाटे के वित्त प्रबन्ध का सही प्रकार से प्रबन्ध नही किया जा सका है। अतः भारत सरकार को इस क्षेत्र में वि"ोश ध्यान दे कर इसका प्रबन्ध सही प्रकार से किया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्था सूचीः–

1–डॉ0 जे0सी0 वार्श्णेय–'लोक वित्त' पेज0 नं083 एसवीपीडी पब्लि"िंग हाउस आगरा

2–डॉ0 टी0एन0 हजेला–राजस्व के सिद्धान्त पेज नं0 346

3–भारत सरकार का बजट सार 2022–23 पेज0 नं0 5

4– भारत सरकार का बजट सार 2022–23 पेज0 नं0 5